

स्वच्छता अभियान

स्वच्छता हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? स्वच्छता की अवहेलना हमें किन घातक बीमारियों से ग्रस्त कर सकती है? अस्वस्थता के चलते कैसे हजारों बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं? हमारे द्वारा फैलाया कूड़ा-करकट पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुँचा रहा है, इन सारे तथ्यों से हम पूर्व में परिचित हो चुके हैं। हमने यह भी जाना है कि अगर कचरे का प्रबन्धन सही तरीके से किया जाए तो वह संसाधन के रूप में परिवर्तित हो सकता है। स्वच्छता हमारी 'संस्कृति' की पहचान रही, वेदों में इसका विवरण है हमने ये भी जाना। इस देश का सबसे दुखद पहलू यह है कि हम भौतिकता और स्वार्थ हित में इस कदर लिप्त हो गये हैं कि हमने अपनी संस्कृति के मूल भाव को विस्मृत कर दिया है।



स्वच्छ भारत मिशन

2 अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'स्वच्छ भारत मिशन' का प्रारम्भ किया। इस मिशन को मूल उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त तथा स्वच्छता के सभी आयामों को प्राप्त करना है। इस मिशन में अनुमानतः 62,000 करोड़ रु. खर्च होंगे। ये मिशन राजनीति से ऊपर और देशभक्ति की भावना से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने हर भारतीय को 'स्वच्छ भारत' बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में शामिल होने की अपील की।

स्वच्छ भारत मिशन को आरम्भ करने का कारण – हम सभी जानते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या 'स्वच्छता' की कमी है। भारत की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत से अधिक खुले में शौच के लिए जाता है जिसके कारण बच्चों की असमय मौत, संक्रमण और बीमारियाँ फैलती हैं।

उद्देश्य

- भारत में खुले में शौच की प्रवृत्ति की पूर्ण समाप्ति।
- अस्वास्थ्यकर शौचालयों को बहाने वाले शौचालयों में परिवर्तित करना।
- हाथों से मल-सफाई व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना।
- लोगों के व्यवहार में बदलाव कर अच्छे स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करना।
- जन-जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ-सफाई के

कार्यक्रम से लोगों को जोड़ना।

- साफ-सफाई से संबंधित सभी व्यवस्था को नियन्त्रित और संचालित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को मजबूत बनाना।
- पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रियाओं निपटान का दुबारा प्रयोग और म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का पुनःचक्रण।

सरकार के प्रयास

स्वच्छ भारत मिशन को सही तरीके से लागू करने के लिए 19 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। समिति के अध्यक्ष वैज्ञानिक रघुनाथ अनंत माशेलकर हैं। रघुनाथ अनंत माशेलकर वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् के पूर्व महानिदेशक हैं। समिति का मुख्य कर्तव्य, विभिन्न राज्यों में स्वच्छता और पानी की सुविधा देने के सबसे श्रेष्ठ और आधुनिक तरीकों पर सुझाव देना है।

परियोजना का क्रियान्वयन :-

स्वच्छ भारत मिशन के दो उप अभियान हैं—

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी

इन दो उप मिशनों के लिए पेयजल, स्वच्छता और ग्रामीण विकास के मंत्रालय, ग्रामीण इलाकों में इसकी जिम्मेदारी लेंगे और शहरी विकास मंत्रालय शहरों में इस मिशन का उत्तदायित्व लेगा।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय हर गाँव को अगले पाँच सालों तक हर साल 20 लाख रुपए देगा। इस मिशन के तहत सरकार ने हर परिवार में व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12,000 रुपए तय की है। एक अनुमान के मुताबिक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस मिशन पर 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे।

स्वच्छ भारत मिशन के शहरी क्षेत्र में हर घर में शौचालय बनाने, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाने, ठोस कचरे का उचित प्रबन्धन करने और 4,041 वैधानिक कस्बों के 1.04 करोड़ घरों को इसमें सम्मिलित करने का लक्ष्य है। इसमें सार्वजनिक शौचालय की दो लाख से ज्यादा सीट, सामुदायिक शौचालय की भी दो लाख से ज्यादा सीट उपलब्ध कराने और हर कस्बे के ठोस कचरे का उचित प्रबन्धन करना शामिल है। आम स्थानों जैसे— बाजार, रेलवे स्टेशन के पास, बस अड्डे, पर्यटक स्थलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय बनवाने का लक्ष्य। शहरी विकास मंत्रालय को इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 62,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

इस संपूर्ण योजना में, खर्च होने वाली अनुमानित लागत 1,96,000 करोड़ रुपए है। इस राशि में 12 करोड़ शौचालय बनाए जाएँगे।

स्वच्छ भारत मिशन से कैसे जुड़ें

देश में रह रहे सभी भारतीयों के प्रयासों से देश की धरती को हर गंदगी से दूर करने

की मुहिम का नाम ही 'स्वच्छ भारत मिशन' है। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि कोई भी इस कार्यक्रम में किसी भी समय सक्रिय रूप से सम्मिलित हो सकता है। उसे बस गँदी जगहों की एक तस्वीर लेनी है और उसके बाद उसे उस जगह की सफाई करने के बाद की तस्वीर लेनी है। फिर पहले और बाद की फोटो सोशल मीडिया, वेबसाइटों जैसे फेसबुक, ट्वीटर आदि पर अपलोड कर देनी है जिससे इसी तरह का कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति भी इससे परिचित और प्रेरित हों तथा स्वच्छ भारत के स्वप्न को प्राप्त कर भारत के मान में वैश्विक स्तर पर वृद्धि कर सकें।

■ प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा जो भी इस मिशन को आगे बढ़ाएगा उसे सोशल मीडिया वेबसाइटों पर सरकार द्वारा सराहा जाएगा।

निर्मल भारत की ओर : संकल्पना और कार्यनीति

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 2012 से 2022 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता और सफाई कार्यनीति तैयार की है। इस कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य निर्मल भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए ठोस धरातल पर कार्य करना है और एक ऐसा परिवेश बनाना है जो स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हो।



निर्मल भारत :- निर्मल भारत की संकल्पना में एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई है जहाँ खुले स्थान पर शौच करने की पारंपरिक प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए जिससे प्रत्येक जन, आत्मसम्मान का जीवन निर्वाहित कर सके एवं स्वस्थता की ओर बढ़ सके। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मल भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए विभाग ने आने वाले वर्षों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति बनाई है—

- उन्नत स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबन्धन के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों को प्रचालित करना।
- ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुभेद्य वर्गों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं में सहयोग को उद्दीपित करना और समर्थ बनाना।
- सभी विद्यालयों में स्वच्छ परिसर का निर्माण।

लक्ष्य

■ संपूर्ण स्वच्छता पर्यावरण का सृजन 2017 तक : संपूर्ण स्वच्छता पर्यावरण का सृजन एक स्वच्छ परिवेश की प्राप्ति और खुले स्थान पर शौच त्याग की समाप्ति है। जहाँ मानव मल अपशिष्ट का सुरक्षित रूप से प्रबन्धन और निपटान किया जाता है।

■ उन्नत स्वच्छता प्रथाएँ अपनाना – 2020 तक : स्वच्छता मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को, खास तौर पर बच्चों और देखभालकर्ताओं द्वारा हर समय सुरक्षित स्वच्छता प्रथाएँ अपनाना है।

■ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन—2022 तक : ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन का लक्ष्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन अपनाकर, गाँवों में स्वास्थ्यकर पर्यावरण का निर्माण करना है।

राजस्थान का 'निर्मल भारत' अभियान

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अक्टूबर 2014 में, 'निर्मल भारत' के स्वप्न को साकार करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाया है जो निम्न प्रकार से है:

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण की इकाई लागत को रुपये 10,000 /— से बढ़ाकर रुपये 12,000 /— कर दिया गया है, जिसमें जल की उपलब्धता, पानी का संग्रहण, हाथ धोने एवं शौचालय के स्वच्छता की सुविधा के व्यवस्था भी सम्मिलित है।

2. इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण हेतु अलग से प्रावधान किया जाएगा। आगामी आदेशों तक मौजूदा राशि की व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम) के तहत ही जारी रहेगी।

निर्मल भारत मिशन का उद्देश्य ही ग्रामीण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठोस एवं तरल कूड़ा-कचरा प्रबन्धन के माध्यम से ही व्यवस्था के लक्ष्य को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। गाँव में बेकार पड़ा ठोस कूड़ा-कचरा पंचायतों के लिए आय का एक स्रोत बन सकता है। इससे ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी।

स्वच्छ भारत—स्वच्छ राजस्थान

राजस्थान सरकार, स्वच्छ भारत का अभिन्न भाग बन, राज्य को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार से पचास हजार का कर्जा लेने वाले काश्तकारों के लिए भी, शौचालय बनाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत मार्च 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के कार्यक्रम में ऐसी कई शर्तें जरूरी की गई हैं। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, समाज कल्याण, चिकित्सा, साक्षरता विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत तमाम अधीनस्थ कार्मिकों, संविदा और प्लेसमेंट, कर्मचारियों, मानदेय पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, महात्मा गाँधी नरेगा के मेटों, उचित मूल्य के दुकानदारों को सम्मिलित किया गया है।

बीकानेर जिला राज्य का पहला खुले में शौच से मुक्त जिला 26 जनवरी 2016 को घोषित किया

गया है। राज्य में अजमेर, पाली, चुरू, झुंझुनु, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में प्रेरकों की टोलियां सरपंच के नेतृत्व में गाँव – गाँव जाकर लोगों को खुले में शौच से होने वाले नुकसान एवं शौचालय के उपयोग के फायदों की जानकारी देकर जागरूक बना रही हैं। ग्रामीण स्वयं अपने शौचालय का निर्माण कर उपयोग सुनिश्चित कर रहे हैं। निगरानी समितियाँ सुबह-शाम खुले में शौच जाने वाले को रोक कर उन्हें शौचालय के उपयोग के लिए प्रेरित कर इस अभियान को सफल बनाने में योगदान कर रही हैं। आज राजस्थान में 2110 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।

स्वच्छता मिशन के चलते ही राजस्थान के कई गाँवों में खुले में शौच की प्रवृत्ति को त्यागने के प्रयास हो रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर के गाँव कोरोपुरा की आबादी 700 के करीब है। स्वच्छता मिशन से पहले गाँव के कुछ घरों में ही शौचालय बने हुए थे। गाँव के अधिकांश लोग खुले में ही शौच जाते थे। लेकिन जेईएन के पद पर कार्यरत गाँव के ही एक युवक ने, खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए कोरोपुरा गाँव को गोद लिया और ग्रामीणों से घर घर जा कर समझाइश की। उस समझाइश की परिणति है, आज वह गाँव ओडीएफ अर्थात् खुले शौच से मुक्त हो गया है।

राज्य में उदयपुर जिले की पहली खुले में शौच मुक्त घोषित कठार ग्राम पंचायत की सफलता, स्वच्छता के प्रति राज्य और उसके नागरिकों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कठार की सफलता की कहानी की शुरुआत तब से होती है जब 12 जून, 2015 को जिला कलेक्टर श्री आशुतोष पट्टनैकर ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर निकले। वे कठार ग्राम पंचायत की पावड़िया बस्ती में पहुँचे। वहाँ गँदगी का माहौल देखकर वह क्षुब्ध हुए। कलेक्टर ने ग्रामीणों की चाय-नाश्ते की मनुहार तक ठुकरा दी तब वहाँ की सरपंच सुशीला कुँवर ने ठान लिया कि जब तक पंचायत खुले में शौच मुक्त नहीं होगी तब तक वे कुर्सी पर नहीं बैठेंगी। इसे अपने सम्मान से जोड़ते हुए ग्रामीणों ने घरों में शौचालय बनाना शुरू किया। गाँव में गौरव यात्राएँ निकाल कर खुले में शौच मुक्त कराने को लेकर जागरूकता रैलियाँ निकाली गईं। उसके साथ ही गाँव में नुककड़ नाटक द्वारा भी जागरूक किया गया। गाँव के मुख्य मार्गों पर जिनके घर शौचालय नहीं हैं उनका नाम लिखा गया। इस मिशन को तब और बल मिला जब गाँव के स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों ने खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के बारे में गाँव वालों को बताया। इसके चलते ग्रामीणों को खुले में शौच नहीं करने का संकल्प दिलाया गया। इतना ही नहीं, प्रत्येक मरीज की पर्ची पर भी लिखा गया कि उनके घर में शौचालय हो। खुले में शौच से मुक्त होने की धुन ऐसी थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत ने कमर कस ली। जिले के सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों के साथ 'ज़िद करो' अभियान चला कर जिन घरों में शौचालय नहीं है, उन घरों के बच्चों को ज़िद कराई कि उनके घर में शौचालय का निर्माण कराया जाए। इस अभियान ने सफलता पाई और उदयपुर की कठार पंचायत ग्राम के, 1200 घरों में शौचालय का निर्माण हो गया। जल एवं स्वच्छता मंत्रालय एवं और मेलिडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से देश भर में उन जिलों की तलाश की गई जिनमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर काम हुआ। इसके तहत देश में 17 जिलों को चयन किया गया। इस सूची में उदयपुर सहित राजस्थान के तीन जिले सम्मिलित किए गए हैं।

जानने योग्य बातें

■ स्वच्छ भारत आंदोलन की मुहिम आज तक का स्वच्छता से सम्बन्धित किया गया एक बड़ा कदम है। इस अभियान को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए तथा आम जन को इसके प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों सहित लगभग 3 लाख

कर्मचारियों ने इसके प्रारम्भ होने के दिन भाग लिया।

■ इस अभियान से प्रेरणा लेकर 3 जनवरी 2015 को, इंडो-नेपाल डॉक्टर एसोसिएशन ने एक अभियान की शुरुआत की जिसको “स्वच्छ भारत नेपाल अभियान” कहा गया। इसकी शुरुआत इंडो-नेपाल बॉर्डर क्षेत्र सुनौली-बेलिहिया से हुई।

■ क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशी नगर जिले के खेसिया गाँव की नीलम, कलावती, निरंजन, गुड़िया और सीता को जब पता चला कि ससुराल में शौचालय नहीं है तो उन्होंने विरोध किया और कुछ दिनों बाद वे अपने-अपने मायके लौट आईं। उल्लेखनीय है कि 68वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में प्रत्येक घर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय होने की बात कही थी। इन नवविवाहिताओं ने प्रधानमंत्री की बात की ओर संकेत करते हुए सुविधा की कमी को लेकर पतियों और ससुराल वालों का विरोध किया।

स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों के प्रयास :-

“मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और इसके लिए समय दूँगा। हर वर्ष 100 घंटे यानि हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के उस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं न गँदगी करूँगा और न किसी और को करने दूँगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गाँव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गँदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गाँव-गाँव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य सौ व्यक्तियों से भी करवाऊँगा। वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूँगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।”

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को देश के सभी नागरिकों को दिलवाई गई इस शपथ को आप पुनः दोहराएँ और इसके प्रत्येक शब्द को आत्मसात करें।

- अपने विद्यालय के मैदान को साफ करें।
- स्कूल के बगीचों का रखरखाव और सफाई करें।
- अपने गाँव के लोगों को सफाई के प्रति जागृत करें।
- अगर कोई गंदगी फैलाता है तो उसे रोकें और समझाएँ।
- स्वच्छ भारत अभियान के वाहक बनें।

अनुकरणीय

(I) हमारे मन में पुनः-पुनः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या विद्यार्थी, स्वच्छता अभियान में वास्तव में सहयोग कर सकते हैं? यह प्रश्न स्वयं विद्यार्थियों के मन में उपजता है। परन्तु इन सारे प्रश्नों का उत्तर है, राजस्थान के अलवर जिले का गाँव ‘अलवड़ी’। यहाँ का माध्यमिक स्कूल बाहर से आम स्कूल की तरह से लगता है। परन्तु स्कूल में प्रवेश करते हुए उसकी उजली तस्वीर दिखाई देती है। विद्यालय के नियम-कायदों के निर्माण और उनके अनुपालन की निगरानी करने के लिए अभिभावकों की एक 13 सदस्यीय समिति का गठन

किया गया है। जिसके अध्यक्ष सरपंच छोटू खॉ हैं। विद्यालय में एक 10 सदस्यीय 'बाल संसद' का गठन किया गया है। विद्यालय की स्वच्छता से प्रशासन तक के कार्यों में 'बाल संसद' अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। बच्चे हर हफ्ते विद्यालय की स्वच्छता पर एक परिचर्चा करते हैं और उसके अंत में विद्यालय को स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हैं। विद्यालय की दीवारें, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़े पोस्टरों, चित्रों और नारों से अटी पड़ी हैं। यह सब बच्चों द्वारा निबन्ध, वाद-विवाद, चित्रकला, सफाई और स्वच्छता पर प्रतियोगिता के अन्तर्गत तैयार सामग्रियाँ हैं, विद्यालयों में पीने का पानी, टैंकर रखा जाने लगा है।

बच्चे शौचालय के प्रयोग के प्रति जागरूक हो गए हैं। स्वच्छता की परिभाषा को विस्तार देकर बच्चों ने पौधारोपण को भी इसका अंग बना लिया है।

विद्यार्थियों की जगाई गई अलख ने, राज्य के अन्य विद्यार्थियों को एक नई राह दिखाई।



(ii) इसी तरह राजस्थान की एक पंचायत ने मिसाल पेश करते हुए एक अनोखा फैसला किया है। जालौर जिले की आनवजोल ग्राम पंचायत ने फैसला लिया है कि जिस लड़के के घर में शौचालय नहीं होगा, वहाँ कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहेगा।

(ii) क्या आप जानते हैं कि जिस सुलभ शौचालय को आप बस स्टैंड, सार्वजनिक जगहों और अपने नगर के कई हिस्सों में देखते हैं, उसके संस्थापक कौन हैं? चार दशक पूर्व 'सुलभ शौचालय' की शुरुआत हुई। डॉ. विंदेश्वर पाठक ने 'सुलभ इंटरनेशनल' नामक संगठन की स्थापना 1970 में की थी। शौचालय पद्धतियों में बदलाव लाने का काम जब उन्होंने शुरू किया था तो लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएँ थीं पर आज उनका संगठन 'सुलभ इंटरनेशनल' एक ब्राण्ड बन चुका है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने भी अपनी पुस्तक 'मिशन इंडिया' में स्वच्छता के क्षेत्र में उनके योगदान की चर्चा की। गाँधीजी के इन शब्दों की "पहले भारत को स्वच्छ करो, आजादी हम बाद में हासिल कर सकते हैं", ने उन्हें खासा प्रभावित किया और वे गाँधीजी के स्वच्छता मिशन से जुड़ गए। समाज को दिए अपने अमूल्य

योगदान के लिए विंदेश्वर पाठक को राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जिसमें 'एनर्जी ग्लोब पुरस्कार', प्रियदर्शनी पुरस्कार, दुबई अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार, अक्षय ऊर्जा पुरस्कार तथा भारत सरकार की ओर से पद्मभूषण शामिल है।

स्वच्छता के बारे में हम चाहे कितनी भी बातें क्यों न करें, जब तक हम स्वयं यह सुनिश्चित नहीं कर लें कि हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे और जहाँ हमें गँदगी दिखेगी उसे दूर करेंगे तब तक स्वच्छता अभियान सार्थक नहीं हो पाएगा। हमने ऐसे कई उदाहरणों को देखा जहाँ एकल और सामूहिक प्रयासों से, स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल किया गया है। हमारा राज्य आज भी स्वच्छता के संदर्भ में देश के कई राज्यों से पीछे है और यह तभी आगे आ सकता है जब हम स्वच्छता की शपथ को, शब्दों के उच्चारण से न दोहरा कर जीवन में आत्मसात करें। जब इंदौर के आठ वर्ष का वज्रांग स्वच्छता को जीवन में उतार सकता है, आसपास के व्यक्तियों को स्वच्छता हेतु प्रेरित करता है तो आप क्यों नहीं? 'हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह दो घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा।' शपथ की इस पंक्ति को अपने जीवन में उतारिये और देखिए कैसे आपका राज्य स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। आपका देश आपकी पहचान है, स्वच्छता अभियान का यही संदेश है कि आप अपनी पहचान को धूमिल न होने दें।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 'स्वच्छ भारत मिशन' किस वर्ष आरम्भ हुआ?
(अ) 17 सितम्बर 2014 (ब) 16 अक्टूबर 2014
(स) 2 अक्टूबर 2014 (द) 27 जुलाई 2015 ()
2. स्वच्छ भारत मिशन के कितने उप अभियान हैं?
(अ) 2 (ब) 3
(स) 4 (द) 5 ()
3. स्वच्छ भारत नेपाल अभियान किस वर्ष आरम्भ हुआ?
(अ) 2013 (ब) 2015
(स) 2010 (द) 2011 ()
4. सुलभ इंटरनेशनल नामक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई?
(अ) 1970 (ब) 2010
(स) 2005 (द) 1985 ()
5. धौलपुर जिलों की इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत का कौन-सा गाँव खुले में शौच से मुक्त हुआ है?
(अ) कोरीपुरा (ब) अफजलपुर
(स) बीरपुर (द) जानपुरा ()

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. 'स्वच्छ भारत मिशन' किस महापुरुष की जयंती पर प्रारम्भ किया गया?
2. 'स्वच्छ भारत मिशन' समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
3. खुले में शौच से मुक्त, राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा?
4. जालौर जिले की आनवजोल ग्राम पंचायत ने स्वच्छता के संदर्भ में क्या निर्णय लिया है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. स्वच्छ भारत मिशन के तीन उद्देश्य लिखें ।
2. 'निर्मल भारत' की संकल्पना से आप क्या समझते हैं ?
3. राजस्थान का निर्मल भारत अभियान, में शौचालय के निर्माण की लागत, कितनी बढ़ाई गई और उसमें कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं ?
4. सुलभ इंटरनेशनल संगठन की स्थापना किसलिए की गई ?
5. स्वच्छ भारत—स्वच्छ राजस्थान, अभियान के बारे में संक्षिप्त में लिखें ।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. 'स्वच्छ भारत मिशन' के बारे में विस्तार के बताएँ ।
2. उदयपुर जिले की कठार ग्राम पंचायत की सफलता की कहानी लिखें ।
3. 'स्वच्छ भारत मिशन' में विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो सकती है, बताएँ ।

उत्तरमाला : (1) स, (2) अ, (3) ब, (4) अ, (5) अ